

Date: 25.08.2026

To
BSE Limited
Listing Department
P.J Tower, Dalal Street
Mumbai – 400001

Stock Symbol -540047

To
National Stock Exchange of India Ltd.
Exchange Plaza, C-1, Block G
Bandra Kurla Complex,
Bandra (E), Mumbai – 400051

Stock Symbol –DBL

Sub: Submission of copies of newspaper advertisement

Dear Sir/Madam,

Pursuant to Regulation 30 and Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, we are enclosing the copies of newspaper publication regarding Notice to Shareholders for transfer of dividend and shares to Investor Education and Protection Fund Authority ("IEPF") on account of unpaid/unclaimed dividend for FY 2018-19 as published in Business Standard Newspaper (English and Hindi) on Monday, August 24, 2026.

We hereby request you to take the above said information on your record.

Further, the said information is also available on the Company website at www.dilipbuildcon.com.

Thanking you

For Dilip Buildcon Limited

Abhishek Shrivastava
Company Secretary & Compliance Officer

Encl a.a.



ISO 9001:2015

CIN No. L45201MP2006PLC018689

Regd. Office :

Plot No. 5, Inside Govind Narayan Singh Gate,
Chuna Bhatti, Kolar Road, Bhopal - 462 016 (M.P.)
Ph. : 0755-4029999, Fax : 0755-4029998

E-mail : db@dilipbuildcon.co.in, Website : www.dilipbuildcon.com

4 विविध समाचार

निर्माण श्रमिकों को पेंशन देने के लिए ईपीएफओ कर सकता है सेस का उपयोग

अहोना मुखर्जी

नई दिल्ली, 23 अगस्त

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) भवन और अन्य निर्माण श्रमिक (बीओसीडब्ल्यू) सेस से जमा हुए अधिशेष धन का उपयोग करके निर्माण श्रमिकों को पेंशन देने की योजना पर विचार कर रहा है। मामले की जानकारी रखने वाले लोगों के अनुसार प्रस्तावित ईपीएफओ 3.0 प्लेटफॉर्म के हिस्से के रूप में इस पर विचार चल रहा है। ईपीएफओ के केंद्रीय न्यासी बोर्ड (सीबीटी) की बैठक में हुई चर्चा के अनुसार प्रस्तावित योजना के तहत निर्माण श्रमिक के रूप में कम से कम 10 साल काम कर चुके श्रमिकों को पेंशन के लिए पात्र माना जा सकता है। योजना तैयार होने के

बाद इसे सीबीटी के समक्ष विचार के लिए रखा जाएगा।

बीओसीडब्ल्यू सेस के तहत एकत्र किए गए धन के बेहतर उपयोग को सुनिश्चित करने की कवायद के तहत इस प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है। इसका उपयोग कई वर्षों से चिंता का विषय रहा है। सेस निर्माण गतिविधि पर लगाया जाता है और प्राप्त राशि का प्रबंधन राज्य सरकारों द्वारा पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के लाभ के लिए कल्याण बोर्डों के माध्यम से किया जाता है।

सीबीटी में राज्यों के प्रतिनिधियों ने निर्माण श्रमिकों को पेंशन देने के लिए सेस के धन के उपयोग का समर्थन किया है। सीबीटी के उपाध्यक्ष ने बीओसीडब्ल्यू के धन के बेहतर उपयोग के लिए एक

योजना तैयार करने को भी कहा है।

समाचार प्रकाशित होने को भेजे जाने तक ईपीएफओ और श्रम मंत्रालय ने इस सिलसिले में भेजे गए प्रश्नों का जवाब नहीं दिया।

निर्माण श्रमिकों तक सामाजिक सुरक्षा के कवरेज का विस्तार करने के प्रयासों के बीच यह प्रस्ताव आया है। इन श्रमिकों का एक बड़ा हिस्सा असंगठित क्षेत्र में काम करता है और पारंपरिक रोजगार करने वाले श्रमिकों को मिलने वाली सामाजिक सुरक्षा के दायरे से बाहर रह जाता है। भवन एवं अन्य निर्माण कामगार कल्याण सेस अधिनियम, 1996 के तहत बीओसीडब्ल्यू सेस लगाया गया था। राज्य सरकारों कंस्ट्रक्शन कंपनियों से सेस वसूली है और पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के लिए कल्याणकारी



भवन और अन्य निर्माण श्रमिक सेस का बगैर इस्तेमाल किए गए धन को श्रमिक कल्याण में लगाने की योजना पर हो रहा है विचार

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन

योजनाओं में इससे प्राप्त धनराशि का इस्तेमाल किया जाता है। इन योजनाओं में शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा, आवास, मातृत्व लाभ और पेंशन के लिए वित्तीय सहायता

शामिल हो सकती है, जो राज्यों की योजना पर निर्भर है।

बहरहाल इस मद में आए धन का बड़ा हिस्सा राज्य कल्याण बोर्डों के पास बगैर किसी इस्तेमाल के पड़ा

कनाडा से वार्ता को मिलेगी गति

असित रंजन मिश्र

नई दिल्ली, 23 अगस्त

कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने अमेरिका पर नई व्यापार संधि संपन्न करने की कनाडा की क्षमता सीमित करने का आरोप लगाया है। इसकी वजह से उत्तरी अमेरिका के इन दो पड़ोसियों के बीच व्यापार वातां टूट गई है। इसके बाद अब भारत और कनाडा के बीच व्यापार वातां ने एक नया रणनीतिक आयाम ले लिया है।

इस घटनाक्रम की वजह से भारत को समग्र आर्थिक साझेदारी समझौते (सीईपीए) पर बातचीत में नई बढ़त मिल सकती है, क्योंकि सबसे बड़े कारोबारी भागीदार अमेरिका के साथ व्यापारिक संबंधों में तेज गिरावट के बाद कनाडा नए बाजार खोलने की कवायद कर रहा है।

कार्नी ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा, ‘अमेरिका ने अंतिम समय में हमारी अन्य व्यापारिक सौदे करने की क्षमता को प्रतिबंधित करने का प्रयास किया। यह अस्वीकार्य है। कनाडाई कारोबार को अब डेढ़ अरब उपभोक्ताओं तक शुल्क-मुक्त पहुंच प्राप्त है। अगले छह महीनों में हम आसियान से लेकर भारत तक नए व्यापार समझौतों के माध्यम से इस आंकड़े को दोगुना कर देंगे।’



नीति आयोग के सदस्य रह चुके अर्थशास्त्री अरविंद विरमानी ने एक्स पर पोस्ट किया, ‘हमें भारत-कनाडा सीईपीए पर हस्ताक्षर और कार्यान्वयन में तेजी लाने की आवश्यकता है। हमारे पास बर्बाद करने के लिए वक्त नहीं है!’

शनिवार को बातचीत विफल होने के बाद अमेरिका ने 20 अरब डॉलर के कनाडा के वस्तु आयात पर 50 प्रतिशत शुल्क लगा दिया है। वहीं कनाडा ने भी क्रसम खाई है कि वह डॉलर के बदले डॉलर में 8 सितंबर से जवाबी शुल्क लगाएगा। ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव के संस्थापक अजय श्रीवास्तव ने कहा कि कनाडा का अनुभव भारत के लिए एक चेतावनी है, जो अमेरिका के साथ भी व्यापार

रहा है और लाभार्थियों तक नहीं पहुंच पाता है। इसे लेकर समय समय पर सवाल उठते रहे हैं।

राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में भवन और अन्य निर्माण श्रमिक (बीओसीडब्ल्यू) कल्याण बोर्डों के साथ 30 जून, 2024 तक लगभग 5.7 करोड़ श्रमिक पंजीकृत थे।

राज्य सभा में जुलाई 2024 में श्रम मंत्रालय द्वारा दिए गए जवाब के आंकड़ों के अनुसार मार्च 2024 तक बीओसीडब्ल्यू कल्याण बोर्डों ने सेस में 1.12 लाख करोड़ रुपये एकत्र किए थे और 641.9 अरब रुपये खर्च किए थे। इसका मतलब है कि कुल व्यय एकत्र किए गए सेस का लगभग 57 प्रतिशत था। बोर्डों ने बताया कि उनके पास 659.7 अरब रुपये बगैर इस्तेमाल के पड़े

हुए हैं, जिनमें इस धनराशि पर बैंक से मिला ब्याज और अन्य प्राप्तियां भी शामिल हैं। ईपीएफओ के पास विचाराधीन प्रस्ताव के तहत कम से कम 10 साल तक काम कर चुके श्रमिकों को अधिशेष बीओसीडब्ल्यू धन से पेंशन के लिए पात्र माना जा सकता है। इस प्रस्ताव में ईपीएफओ और राज्य सरकारों के बीच तालमेल पर भी सवाल उठते हैं, क्योंकि बीओसीडब्ल्यू के धन का प्रबंधन राज्य स्तर पर किया जाता है। इसलिए किसी भी राष्ट्रव्यापी पेंशन व्यवस्था के लिए राज्यों को अपने संचित धन के उपयोग और पात्र निर्माण श्रमिकों की पहचान के तंत्र पर सहमत होने की आवश्यकता होगी।

यह पेंशन प्रस्ताव व्यापक ईपीएफओ 3.0 पहल का हिस्सा है,

जिसके तहत सेवानिवृत्ति निधि निकाय अपने प्रौद्योगिकी मंच को आधुनिक बनाने और सामाजिक सुरक्षा तक पहुंच का विस्तार करने का प्रयास कर रहा है। प्रस्तावित मंच में श्रमिकों की उन श्रेणियों को भी शामिल किए जाने की उम्मीद है, जो पारंपरिक औपचारिक कार्यबल से बाहर हैं।

सीबीटी ने निर्माण श्रमिकों के लिए कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी) कवरेज का विस्तार करने के प्रस्ताव पर भी विचार किया, जिसमें उनके ईएसआईसी योगदान को बीओसीडब्ल्यू फंड से भुगतान करने की संभावना है। इससे श्रमिकों को पेंशन कवरेज के अलावा चिकित्सा और अन्य सामाजिक-सुरक्षा लाभों तक पहुंच मिल सकती है।

आईएएस अधिकारी गंगवार के परिसरों पर ईडी के छापे

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने कर्नाटक लोक सेवा आयोग (केपीएससी) द्वारा आयोजित एक परीक्षा में कथित अनियमितताओं से जुड़े धनशोधन मामले की जांच के तहत रविवार को आईएएस अधिकारी ज्ञानेंद्र कुमार गंगवार के बेंगलूरु और उत्तर प्रदेश के बरेली स्थित परिसरों पर छापेमारी की। हालाँकि, यह तत्काल पता नहीं चल सका कि केंद्रीय जांच एजेंसी को अधिकारी इन परिसरों में मिले या नहीं। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। शनिवार को कुछ घंटों के लिए गंगवार के “लापता” होने की खबर सामने आने के बाद विवाद खड़ा हो गया था। बाद में कर्नाटक के गृह मंत्री प्रियंक खरगे ने इन खबरों का खंडन करते हुए स्पष्ट किया कि गंगवार अपने पिता की तबीयत से जुड़ी पारिवारिक आपात स्थिति के कारण उत्तर प्रदेश स्थित अपने पैतृक स्थान पर थे।

गंगवार भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) के 2016 बैच के अधिकारी हैं और वर्तमान में कर्नाटक के उद्योग एवं वाणिज्य विभाग में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम निदेशक के पद पर तैनात हैं। वह इससे पहले केपीएससी में परीक्षा नियंत्रक के पद पर कार्यरत थे और इस साल मार्च में उन्हें इस पद से हटा दिया गया था।

भाषा

विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ा , लेकिन रुपये को मजबूती नहीं

अंजलि कुमारी

मुंबई, 23 अगस्त

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) की रियायती स्वैप योजनाओं के माध्यम से आई विदेशी मुद्रा का रुपये पर बहुत कम असर पड़ा है। बाजार प्रतिभाषियों ने कहा कि विदेश से आया डॉलर मुख्य रूप से हाजिर बाजार में आने के बजाय केंद्रीय बैंक के भंडार में जमा हो गया है।

जब 8 जून को यह योजना शुरू की गई थी, तब रुपया 95.71 प्रति डॉलर पर था और 21 अगस्त को भी इसी स्तर पर बंद हुआ।

इसी तरह की रियायती स्वैप योजना 2013 में लाई गई थी, उस समय रुपया 8.8 प्रतिशत मजबूत हुआ था।

एक प्राइवेट बैंक के ट्रेजरी प्रमुख ने कहा, ‘इस बार आने वाले डॉलर सिस्टम में जारी नहीं किए जा रहे हैं, जबकि 2013 में सिस्टम में डॉलर आए थे।’ रुपया अभी भी वैश्विक

संकेतों के मुताबिक चल रहा है। डॉलर की आवक का बहुत कम या कुछ भी असर नहीं हुआ है क्योंकि इसके लिए डॉलर का बाजार में आना जरूरी है। सिस्टम में डॉलर की मात्रा उतनी ही बनी हुई है।

इस स्वैप सुविधा के तहत बैंक एफसीएनआर-बी जमा के माध्यम से जो डॉलर जुटाते हैं, उसे रिजर्व बैंक के पास जमा कर रुपये ले लेते हैं। इससे बैंकिंग व्यवस्था में रुपये के हिसाब से नकदी बढ़ी है, जबकि विदेशी मुद्रा रिजर्व बैंक की विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियों (एफसीए) में जुड़ा गई है।

ताजा आंकड़ों के मुताबिक रिजर्व बैंक की विविध डॉलर-रुपये फॉरवर्ड स्वैप सुविधा के तहत 2.1 अरब डॉलर के कुल 72.85 अरब डॉलर आए हैं। इसमें से एफसीएनआर-बी जमा का हिस्सा 65.40 अरब डॉलर (कुल आवक का लगभग 90 प्रतिशत) था, जबकि ऑफशोर फॉरेन करेंसी बॉन्ड (ओएफसीबी) और बाह्य



हाजिर बाजार में डॉलर न आने से रुपया चला अपनी चाल

वाणिज्यिक उधारी (ईसीबी) के माध्यम से क्रमशः 4.86 अरब डॉलर और 2.59 अरब डॉलर आए हैं।

इस आवक से हाजिर बाजार में डॉलर की आपूर्ति स्वतः नहीं बढ़ी। बाजार में विदेशी मुद्रा तभी आ सकती थी, जब रिजर्व बैंक ने हाजिर बाजार में हस्तक्षेप कर क्रमिक रूप से डॉलर जारी किया होता या अपना फॉरवर्ड पोजिशन घटाया होता।

पर्यटन व निवेश के जरिये जापान से बढ़ रहा संबंध

वीरेंद्र रावत

लखनऊ, 23 अगस्त

उत्तर प्रदेश ने जापान के यामानाशी प्रांत के 200 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल के सामने अपनी ऐतिहासिक और सांस्कृतिक पर्यटन क्षमता को पेश किया है।

प्रतिनिधिमंडल की पांच दिवसीय यात्रा का उद्देश्य उत्तर प्रदेश और जापान के बीच निवेश तथा कारोबारी संबंधों को मजबूत करना भी है। प्रतिनिधिमंडल पर्यटन, विनिर्माण, हरित हाइड्रोजन, कौशल विकास और प्रौद्योगिकी के

क्षेत्र में अवसर तलाश रहा है। यामानाशी प्रांत के गवर्नर कोटोरो नामासाकी और उपराज्यपाल जुनिची इशिदेरा के नेतृत्व में निवेशकों और कारोबारी नेताओं का प्रतिनिधिमंडल नई दिल्ली में शुरुआती कार्यक्रम के बाद आगरा, लखनऊ, ग्रेटर नोएडा और वाराणसी का दौरा कर रहा है।

प्रतिनिधिमंडल ने ग्रेटर नोएडा के गलगोटिया विश्वविद्यालय में कार्यक्रम में शामिल होने के बाद ताजमहल का दौरा किया। इस दौरान गलगोटिया विश्वविद्यालय के साथ 2 समझौते भी हुए।

डिस्कलेमर- बिजनेस स्टैंडर्ड में प्रकाशित समाचार रिपोर्ट और फीचर लेखों के माध्यम से बाजारों, कॉरपोरेट जगत और सरकार से जुड़ी घटनाओं की निष्पक्ष तत्वेीर पेश करने का प्रयास किया जाता है। बिजनेस स्टैंडर्ड के निबंधन एवं जानकारी से पुरे परिस्थितियों के कारण वास्तविक घटनाक्रम भिन्न हो सकते हैं। समाचार पत्र में प्रकाशित रिपोर्टों के आधार पर पाठकों द्वारा किए जाने वाले निवेश और लिए जाने वाले कारोबारी निर्णयों के लिए बिजनेस स्टैंडर्ड कोई जिम्मेदारी नहीं लेता है। पाठकों से स्वयं निर्णय लेने की अपेक्षा की जाती है। बिजनेस स्टैंडर्ड के सभी विश्लापन सद्भाव में स्वीकार किए जाते हैं। इनके साथ बिजनेस स्टैंडर्ड ने तो जुड़ा हुआ है और न ही उनका समर्थन करता है। विश्लापनों से संबंधित किसी भी प्रकार का दावा संबंधित विश्लापनदाता से ही किया जाना चाहिए। नै, बिजनेस स्टैंडर्ड प्रा. लि. का सर्वाधिकार सुरक्षित है बिजनेस स्टैंडर्ड प्रा. लि. से लिखित अनुमति लिए बगैर समाचार पत्र में प्रकाशित किसी भी सामग्री का किसी भी तरह प्रकाशन या प्रसारण निषिद्ध है। किसी भी व्यक्ति या वैधानिक निकाय द्वारा इस प्रकार का निषिद्ध कार्य किए जाने पर दीवानी और फौजदारी कार्यवाही शुरु की जाएगी।